इन्दिरा-मुजीब समझौते से संबंधित पत्रों का प्रकाशित किया जाना

553. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत और बंगला देश के विदेश मंत्रियों के बीच हुए पत्र व्यवहार के आधार पर इन्दिरा–मुजीब समझौते के अन्तर्गत तीन बीघा क्षेत्र के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिये वर्ष 1982 को आधार वर्ष मानने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उक्त व्यवस्था करने से पूर्व जनता की जानकारी के लिए इन पत्रों को प्रकाशित करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) (i) 1974 के भूमि सीमा करार पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री —श्रीमती इंदिरा गांधी और बंगला देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री—शेख मुजिबुर रहमान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ; इसमें तीन बीघा के पास बंगलादेश के पानवाड़ी मौजा (थाना ; पत्ग्राम) को दाहाग्राम से जोड़ने के लिए करीब 178 मीटर × 85 मीटर का क्षेत्र भारत द्वारा बंगला देश को लीज पर दिए जाने का प्रावधान है ।

(ii) भारत के विदेश मंत्री और बंगला देश के विदेश-कार्य मंत्री के बीच 1982 में आदान-प्रदान किए गए पत्रों के आधार पर भारत और बंगला देश के बीच लीज की शर्तों पर समझौता हुआ था ।

(iii) 26 मार्च 1992 को पत्रों के आदान-प्रदान के जरिये भारत और बंगला देश की सरकारों ने आपस में स्वीकार कर लिया है कि लीज 26 जून, 1992 से लागू होगी ।

(ख) और (ग) भारत और बंगला देश के विदेश मंत्रियों द्वारा 1982 में एक-दूसरे को भेजे गए पत्रों को पहले ही सार्वजनिक कर दिया गया है ।

Government's Reaction on the Malaysian Demand for Restructuring on Security Council

554. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Malaysia had recently made a strong plea for restructuring the UN Security Council;

(b) whether Malaysia had demanded the restructuring of the Council in such a manner so as to give proper representation to the numerically large number of countries of the South;

(c) if so, what are the details in this regard; and

(d) what is the reaction of Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Speaking in the UN General Assembly on December 12, 1991 the Malaysian representative strongly urged that the reform process of the UN must involve the Security Council in a way that would not only reflect a more equitable geographical representation, but also contributes to the strengthening of the democratisation process within the UN system.

(d) Government supports the democratisation of the UN system, including a wider representation of its membership in the Security Council.